एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक

एआईआईबी

चुनौतियों पर एक नजदीकी झलक

एआईआईबी क्या है ?

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेण्ट बैंक (एआईआईबी) विश्व बैंक और एशियन डेवलमेंट बैंक (एडीबी) के जैसे ही एक नई अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो 2016 मे शुरू हुई इसका आरम्भ चीन के नेतृत्व ने किया है। इसकी प्रारम्भिक पूंजी 6.5 लाख करोड़ रूपये है जो एडीबी (10.2 लाख करोड रूपयें) के दो तिहाई और विश्व बैंक (16.38 लाख करोड रूपयें) के लगभग आधी पूंजी के बराबर है।

इसके सदस्य कौन है ?

वर्तमान मे पूरे दुनिया से एआईआईबी के लगभग 86 देश सदस्य हैं। जापान और यूएसए जैसे बड़े देश अभी भी इसके सदस्य नही है। चीन के बाद भारत इसका सबसे बड़ा शेयर धारक है। एआईआईबी ही एक ऐसी अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसमे विकासशाील देशों का सबसे अधिक वोट शेयर है।

इसकी प्राथमिका क्या है ?

एआईआईबी की प्राथमिकता एशिया और अन्य देशों मे मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी को कम करना है। जिसमे रेलवे, पावर सेक्टर मे वितरण और ट्रासमिशन, ट्रांसपोर्ट और सड़को का विस्तार करना है।

क्या अन्य बैंको के लिये एआईआईबी एक चुनौती है ?

एआईआईबी की पूरक भूमिका है ना कि दूसरी बैकों से प्रतिर्स्पधा करना। एआईआईबी के कुल 25 परियोजनाओं में से 14 विश्व बैंक और एडीबी के साथ को–फाइनेन्स किया है। जिसमे एआईआईबी ने मौजूदा बहुपक्षीय विकास बैंक के मानकों और सुरक्षा नीतियों को ही को–फाइनेन्स के लिये अपनाया है।

एआईआईबी के मुदद्धे क्या है ?

एआईआईबी ने बिना अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा की नीतिया बनाये ही परियोजनाओं को फाइनेन्स करना शुरू किया है जो पर्यावरण और समुदायों को ओर ज्यादा प्रभावित कर सकता है। प्रस्तावित क्षेत्रों मे इसके मुख्यरूप से प्रभावो की प्रकृति मे लोगो का विस्थापन, उनकी आजीविका को नश्ट करना, भूमि अधिग्रहण और पारिस्थितिक तंत्रों को नश्ट करना आदि होगें। सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए बैक को उन परियोजना मे जिसमें वे फाइनेन्स करते है उसमें मानवाधिकार जोखिमों की पहचान करने और उनको संबोधित करने की आवश्यकता नही होती है क्योकि एआईआईबी परियोजना मूल्याकंन के लिये को–फाइनेन्सर पर निर्भर रहता है। एआईआईबी के पास अभी भी कोई शिकायत निवारण तंत्र नही है लेकिन परियोजनाओं को मंजूरी दिया जा रहा है। एआईआईबी ने कई मध्यवर्ती फाइनेन्स संस्थाओं के माध्यम से परियोजना को मंजूरी दी है लेकिन वह पूँजी किन परियोजनाओं मे जा रहा कोई स्पश्टता नही है। एआईआईबी की प्रस्तावित ने ानल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेण्ट फडं (एनआईआईएफ) योजना भी रूके हुये थर्मल पावर परियोजनाओं मे पूँजी लगाने की कोशिश कर रही है। मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से फाइनेन्स करने मे पारदर्शिता और गैर जबावदेही के कई गंभीर मुदद्धे जुडे है।

एआईआईबी को समुदाय कैसे प्रभावित एवं उसके साथ संवाद कर सकते है ?

वर्तमान मे एआईआईबी के पास ऋण की मंजूरी देने और उसका मूल्यांकन करने मे समदाय और सिविल सोसाइटी को साथ लेकर चलने का कोई भी पारदर्शी उपाय मौजूद नही है। प्रस्तावित जन सूचना नीति और प्रभावित लोगों का शिकायत निवारण तंत्र बैक की बेवसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन यह अभी भी पूरे नही है और वह अभी भी मौजूदा बहुपक्षीय विकास बैंक से ही लिये गये है। समुदायो को इसको पूरा करने हेतु दबाव बनाना चहिये कि परियोजना चिन्हित करने और उसकी मंजूरी देने से पहले संपूर्ण और पूर्वसूचित जनसहमति और परामर्श लेना चाहिये।

भारत में एआईआईबी के निवेश क्या हैं ?

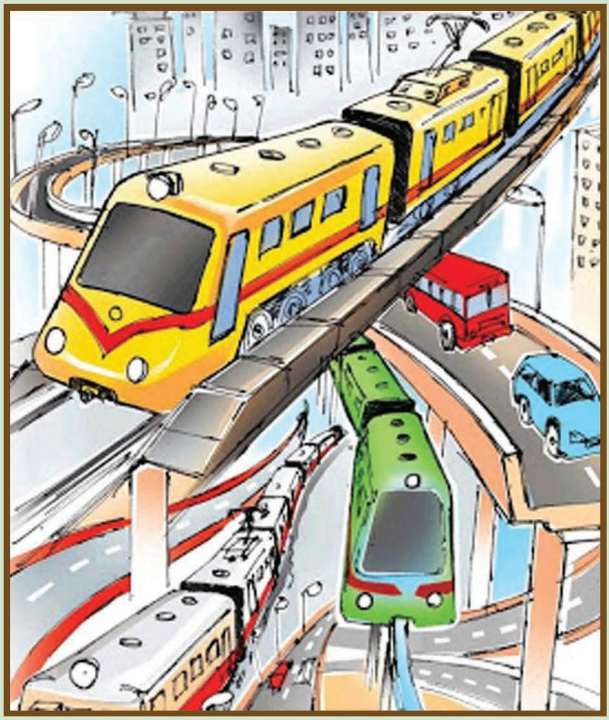

भारत निवेश को देखते हुये चहेता स्थान रहा है। वर्श 2017 तक एक अरब अमरीकी डॉलर से भी ज्यादा लिया गया कर्ज और तीन अरब डॉलर अभी पाइपलाइन मे होने के साथ अब तक एआईआईबी का सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है।

बहु–क्षेत्रीय परियोजना	–	2025 करोड़ रूपये
यातायात	–	8,520 करोड़ रूपये
ऊर्जा	–	1,698 करोड़ रूपये
सिंचाई व बाढ़	–	9,47 करोड़ रूपये
कुल अनुमोदित परियोजनायें	–	7,013 करोड़ रूपये
कुल प्रस्तावित परियोजनायें	–	7,483 करोड़ रूपये

हमें अंर्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, खासकर एआईआईबी के साथ समीक्षात्मक रूप से संवाद करने की क्यो जरुरत है ?

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एआईआईबी और नया विकास बैंक (एनडीबी) (भारत हाल ही में यूरोपियन निवेश बैंक (ईआईबी) का भी सदस्य बना है पर उसका निवेश अभी शुरू होना बाकी है) और द्वि–पक्षीय संस्थान जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये जापान बैंक (जेबीआईसी), जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्थान (जेआईसीए), चाइना डेवलपमेटं बैक और चाईनीज एक्जिम बैंक ने अपने कर्जों को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी और ऊर्जा परियोजनाओं में कई गुना बढ़ाया है।

ऐसे कर्ज वर्तमान नीतियाँ, भूमि, जल, जंगल, खाद्य, आजीविका, संरचना, और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, यहाँ तक कि वह हवा जिसे हम हर पल साँस लेते हैं, पर सीधे तौर पर असर डालते हैं।

यह सभी मुद्दे हमारे चिंता को एक भयानक स्तर तक बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते हम विकास के नाम पर हो रहे तेजी से 'आर्थिक सुधारों' पर सोचने और कुछ कार्यवाही करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसा विश्व बैंक और एडीबी अपने विकास के एजेंडे का दावा गरीबी और असमानता के नाम पर करते हैं, उसके विपरीत एआईआईबी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में फाइनेन्सं करने में अपने भारी रुझान पर कोई पर्दा नहीं डालता है। इस खतरनाक रूप से जल्दबाजी में बिना विचार विमर्श किये हुए निवेश, जिसमें कमजोर सुरक्षा–नीतियाँ और उचित मूल्यांकन का अभाव है, ऐसे निवेश को कड़ी चुनौती दी जानी चाहिये और सिविल सोसाइटी द्वारा इनका सावधानी पूर्वक निगरानी रखने की आवश्यकता है।

वर्किंग ग्रुप ऑन आईएफआईस द्वारा प्रकाशित
संपर्क करें: wgonifis@gmail.com \ www.wgonifis.net
सिर्फ निजी वितरण हेतु